SHRI M. A. BABY: Will the Minister utilise the expertise of fire-fighting in the Congress?...(*Interruptions*)...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Will they take the help of some foreign companies to do some fire-fighting within the Congress?...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Chairman, Sir, I wish the Minister were equally enthusiastic about sharing not only enlightenment but also many other things that accrue to him. Sir, let me come to the substantial question. This blow-out has taken place in the most fertile part of Andhra Pradesh. Sir, a lot of damage was caused to the crops. Sir, I would like to know as to what compensation has been paid to them. There is something to add, Sir. The soil, which is very fertile, has suffred enormous damage in terms of nutrition and many other things. The water has also got damaged. I would like to know what environmental steps have been taken to undo this damage and provide compensation to the owners of the land whose land quality has been damaged?

CAPT. SATISH SHARMA: Sir, the evacuation, rehabilitation and relief measures are being undertaken by the ONGC in close co-ordination with the District Administartion. The Collector of East Godavari district constituted three committees consisting of representatives from the State Revenue Department and the ONGC. The first committee is the Committee for enumeration and assessment of damage to public and private Proporties, like coconut trees, crops etc in the affected areas consequent on the blow-out; the second is the Committee for assessing damages to the houses in the areas affected by the blow-out, and the third is the Committee for assessment of health problems in the area of the blow-out. Then, the information I have is that 2,000 healthy coconut trees, and 50 mango trees in the vicinity have been affected; 16 acres of paddy crop have been affected. Rs. 45 lakhs have been deposited with the District Administration for paying the compensation. Plaints of individuals, as called by the Committee, are being received and assessed. I can assure the hon. Member, for whim I have the highest regard, that the compensation will be given to them. The process is on. As regards the other part of the question the hon. Member has asked, about the environmental damage, I am glad to inform the House through you that as this is a dry high-speed gas, we had very closely monitored what environmental effect it had on the area. Fortunately, Sir, the hydrocarbons are fullly burnt and sulphur dioxide and other toxic materials have not really been detected. We are having the environmental review from our Goa institute. Also, other independent environmental instiutions have been therein place trying to detect if there is any environmenetal damage. I am glad to inform you that no such damage is there.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, may be the Minister is right. But, I have come to know through the Agriculture Department of the Andhra Pradesh Government that they have reported the damage caused to the quality of the land. Therefore, I would request the Minister to recheck with the Andhra Pradesh Government as to the damage caused environmentally to the land.

CAPT. SATISH SHARMA: Sir, I have given the assurance through you to the hon. Member. Certainly, I would check up with the State Government and the Agriculture Department to see if there is any damage. I assure that full compensation would be paid.

Corruption in Passport Office

"43. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Passports issued to wrong persons, who misused it and trial is on", appearing in The Times of India dated the 2nd December, 1994.

(b) if so, the details thereof;

(c) whether this matter has been enquired into as to how the passports were issued to other persons,

(d) how many cases of this type have taken place in each of the last three years; and

(e) the number of staff members involved in the aiding and abetting of such crimes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) to (e) A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

Yes, Sir.

The facts of the case are as follows:

One passport No. H-090672 dated 11-5-1990 was prepared in favour of Shri Manoj Kumar Gupta but it fell in wrong hands and was misused. When Mr. Gupta stated that he had not received the passport, he was issued another passport bearing No. H-670200 dated 20-8-1990 which bore the endorsement that he had earlier held passport No. H-090672 dated 11-5-1990 which was returned to him. Shri Gupta returned the passport to Regional Passport Office, Delhi for correction of this endorsement. After investigating the matter, Regional Passport Office, Delhi revoked both these passpirts, Instructions have been issued Shri Manoj Kumar Gupta a fresh passport without charging any extra fee. DCP Crime Branch, Delhi as well as judicial Magistrate, Saidapet, Tamil Nadu and the applicant have been informed accordingly.

Yes, Sir. It has been found that the passport was prepared in the favour of Shri Manoj Kumar Gupta. However, it went into wrongful possession.

This is the noly such case that has been brought to Government,s attention

Following investigation, two casual workers in Regional Passport Office, Delhi were dismissed.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति महोदय, यह जितना अजीब केस है उतना ही अजीब इसका जवाब है। एक पासपोर्ट श्री मनोज कुमार गुप्ता के नाम बनाया गया और मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि वह गलत हाथों में पड़ गया परन्तु जवाब में यह नहीं बताया गया कि वह आदमी स्मग्लिंग में पकड़ा गया और असली मनोज कुमार गुप्ता के घर पर कस्टम ने रेड किया और पांच साल से यह केस चल रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि गलत आदमी के हाथों में पड़ गया था और जो असली मनोज कुमार गुप्ता है उसका कोई कसूर नहीं था, वह पांच साल से मद्रास में केस लड़ रहा है, तो पांच साल तक किसी ने उसको इन्फार्म क्यों नहीं किया ? अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब यह बतायें–आज कोई स्मग्लर, कोई एंटी सोशियल एलीमेंट, कोई पाकिस्तानी एजेंट या इसी तरह के दूसरे लोग यदि चाहें तो उनको एक दिन में पासपोर्ट मिल जाता है और जो असली आदमी है उनको महीनों तक पासपोर्ट नहीं मिलता–कि इस केस में जब कि आपको पता चल गया तो आपने इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की ?

श्री आर० एल० भाटिया : यह जो केस है, इसमें हमारे डिपार्टमेंट से पासपोर्ट इश्यू हुआ। लेकिन मनोज कुमार गुप्ता का कहना है कि उसको पासपोर्ट नहीं पहुंचा। उसके बाद जब हमने उसको दूसरा पासपोर्ट इश्यू कर दिया, तो इस पर उसको यह एतराज था क्योंकि उसमें यह मेंशन था कि यह पासपोर्ट पहले इश्यू हो चुका है और हमारे कायदे के मुताबिक अगर कोई पासपोर्ट डुप्लीकेट इश्यू होता है तो उसमें पहले पासपोर्ट का वर्णन करना जरूरी होता है जिस पर उसने इसी पर ऐतराज किया। यह जो केस आप कह रहे हैं, वह जो पहला पासपोर्ट था किसी गलत हाथों में चला गया और उसका इस्तेमाल होता रहा। हमारे नोटिस में उस वक्त बात आई जब वह आदमी जो एक स्मगलर था और

मद्रास में पकड़ा गया। जब हम पासपोर्ट इश्यू कर देते हैं तो हमारी कोई जानकारी नहीं होती कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। हमारे पास जब कम्प्लेंट आती है तो उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं। जब हमारे नोटिस में यह बात आई, हमने वह पासपोर्ट कैंसिल कर दिया और उसके बाद जो कोर्ट की कार्रवाई है वह जारी है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि इस मामले में दो केज्यूअल वर्कस को डिसमिस कर दिया गया। यह इतना बड़ा मामला है जिसमें स्मगलिंग का मामला भी इंवोल्वड है, उसकी फाईल गायब है। बाद में वह स्मगलर पकड़ा गया। इस तरह के ऐसे सैकड़ों केसेज हो रहे हैं। इतना बड़ा रेकेट चल रहा है कि जिस रेकेट में जेन्यूअन आदमी को पासपोर्ट न देकर अन्य लोगों को दे दिया जाता है और वह फोटो बदल लेते हैं। पाकिस्तानी एजेंट भी ऐसे जाली पासपोर्ट पर काम कर रहे है, मिलिटेंट भी काम कर रहे हैं, स्मगलर्स भी कर रहे हैं। आप सी०बी० आई० से इसकी इंक्वायरी क्यों नही कराते? दो केज्युल वर्कर्स जो डेली वेजेज पर थे, उनको डिसमिस करके क्या आप समझते हैं कि फाईलें उन्होंने गायब करदी? पांच साल से यह केस चल रहा है और पांच साल के बाद आपने दो केज्युअल वर्कर्स को डिसमिस कर दिया और दूसरी तरफ उस आदमी को इतनी भीषण मानसिक और शारीरिक यातनायें हुई, लाखों रुपया मुकदमा लड़ने में लग गया। अब आप कहते हैं कि बिना फीस के आप तीसरा पासपोर्ट ले लो। यह कैसा मजाक किया जा रहा है, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट कीजिए?

श्री आर० एल० भाटिया : जैसा कि आपने कहा कि पांच साल के बाद यह मामला आया, मैंने अर्ज की कि जब तक हमारे पास कोई कम्प्लेंट नहीं आए, तो उसके पहले हम कोई एक्शन कैसे ले सकते हैं? आप जानते है इस बात को। ज्यों ही यह केस मद्रास कोर्ट में पेश हुआ और हमारे नोटिस में आया... (व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : 1990 में पेश हुआ और आज 95 हो रहा है।

श्री आर० एल० भाटिया : अगर वह पांच साल के बाद कोई जुर्म करता है और हमारे नोटिस में आता है तो उस पांच साल मे हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अभी तक आपने मद्रास हाई कोर्ट को नहीं लिखा है कि यह केस जेन्युअन नहीं है, यह आदमी बेकसूर है जिसको आप नया पासपोर्ट दे रहे है।

श्री आर० एल० भाटिया : देखिए, यह कोर्ट का मामला है। अगर हमें कोर्ट एज विटनैस काल करेगी तो हम जरूर यह कह देंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह क्या बात हो रही है। सी०बी०आई० से इंक्वायरी करायेंगे कि यह कैसे हो रहा है?

श्री दिग्विजय सिंह : यह क्वेश्चन तो एडमिट ही नहीं होना चाहिए था।

There is no supplementary We can go to the next question.

MR. CHAIRMAN: I have allowed the other Member to put a supplementary

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सभापति महोदय, पारपत्र कार्यालय मे भ्रष्टाचार, पारपत्रों को देरी से जारी करने की शिकायतें आम तौर पर सुनते रहे है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि आपके मंत्रालय से संबंधित स्थाई समिति ने यह सिफारिश की है कि पारपत्रों को जारी करने का काम गृह मंत्रालय को सौंप देना चाहिए, क्योंकि पुलिस द्वारा सत्यापन करना तथा अन्य तमाम चीजों के बारे में आपके मंत्रालय के अंतर्गत काम करने में दिक्कत होती है, जो कि गृह मंत्रालय के पास पूरी मशीनरी है। तो मेरा यह जानना है कि आप इस पर विचार कर रहे है? क्या आपने स्टैंडिंग

कमेटी की इस रिकमेंडेशन पर विचार किया है? अगर नहीं किया तो क्या करने वाले हैं और इस पर आपका नजरिया क्या है, यह मैं जानना चाहती हूं?

श्री आर. एल. भाटिया : स्टैंडिंग कमेटी ने काफी सिफारिशें हमको दी हैं। हम उन पर गौर कर रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : यह तो गौर हो कर रहे हैं तो क्या पूछें? कितने दिन तक गौर करेंगे, यह बतला दीजिए।

श्री आर. एल. भाटिया : स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अभी तो आई है। उस पर अमल हो रहा है।

श्री चतुरानन मिश्र : हम कह रहे हैं कि कितने दिन तक गौर करेंगे?

श्री आर. एल. भाटिया : मैं इतना ही कह सकता हूं कि उस पर गौर हो रहा है और जल्दी से जल्दी हम इसको कर रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : कोई टाईम लिमिट तो बताएं?

श्री आर० एल० भाटिया : फिर आप मुझे गवर्नमेंट में पकड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यह जो रिकमेंडेशनस हैं बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस हैं जो हमारे पास आई हैं। इससे पासपोर्ट इश्यू करने में सुधार होगा। इसलिए हम गौर करके, डिसकस करके उस पर अमल करेंगे।

Setting up of an oil refinery in the east coast

†14. SHRI S. AUSTIN:

SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: †

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state,

(a) whether the Indian Oil Corporation Ltd. propose to set up an oil refinery in the east coast;

(b) if so, the capacity of the proposed refinery;

(c) the location of the refinery; and

(d) the progress made so far in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (c) Indian Oil Corporation has in principle approval to set up a 6 MMTPA joint venture refinery in the East coast. During the feasibility study, the refinery was proposed to be located at Daitari. However, exact location of the refinery will be decided based on Detailed Feasibility Report.

(d) Government has accorded an investment approval to IOC for preparation of Detailed Feasibility Report for the project.

SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: The hon. Minister has said that 6 MMTPA refinery is to be set up in the east coast. It is learnt that three crude oil refinery companies of GSA have recently signed a production-sharing contract with the Government of Indian for expedition of Kaveri Basin on the east coast. Therefore, will the Minister clarify whether the joint venture refinery is in collaboration with any multi-national?

CAPT. SATISH SHARMA: Sir, as far as the IOC refinery is concerned, it is one of the three joint venture refineries between the public sector on the one hand and a multi-national or foreign collaborator, on the other. The BPCL and the HPCL have already joined the Oman Oil Corporation to set up tyo refineries. The Government has opted for the time being for the IOC to go on on its own. They are carrying out a feasibility study and they will be selecting a partner. However, negotiations are going on with Kuwait Petroleum Corporation for a joint venture

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri V. Rajan Chellappa